JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जी-20 एवं भारत

डॉ.कल्पना वैश्य सह प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला
एवं शोध केंद्र,महाराजा छत्रशाल
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर,(मध्य प्रदेश)

शोध सारांश - एशियाई वित्तीय संकट के समय गठित सन 1999 में वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय स्थायित्व आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु ,व्यवस्थित औद्योगीकृत,विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित् मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा मिलकर जी-20 समूह की स्थापना की गई थी। अपने प्रारंभिक समय से ही जी-20 समूह द्वारा नियमित रूप से वित् मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठकों का आयोजन वैश्विक वित्तीय संवर्धन तथा स्थायित्व बढ़ाने के उपायों को को प्रोत्साहित करने और सतत् आर्थिक वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से किया जा रहा है । जी -20 समूह प्रारंभिक वर्षों में वित् मंत्रियों का मंच था। 2008 मैं इसे शिखर सम्मेलन का रूप दिया गया, जिसमें राष्ट्र प्रमुखों का प्रतिनिधित्व होने लगा। इस समूह में विकसित राष्ट्रों में जहां अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, कनाडा एवं जापान तो वहीं विकासशील राष्ट्रों में भारत, चीन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको,ब्राज़ील तथा रूस आदि शामिल हैं । मध्य नवंबर 20,22 में बाली शिखर सम्मेलन के अंत मैं जिस जी -20 की अध्यक्षता का जो हथोड़ा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सौंपा गया, एक दिसम्बर को भारत ने औपचारिक रूप से जिस जी जी -20 की ज़िम्मेदारी सँभाली है, वह समूह वैश्विक की आबादी का 60% GDP का 85% तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% है।बाली शिखर सम्मेलन में विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं भारत ने यह भी ठाना कि अपनी अध्यक्षता में वह वैश्विक चुनौतियों पर खरा उतरेगा और ऐसी छाप छोड़ेगा कि विश्व उसका लोहा मानेगा ।इस सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं के जमावड़े से कहा था कि कोविड-19 के बाद के दौर के लिए नई व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है।मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारत की जी ट्वेंटी की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी। निसंदेह यह चार शब्द

जी ट्वेंटी के अध्यक्ष के रूप में भारतीय दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली डिक्लेरेशन जिसे सभी जी ट्वेंटी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। इन सिद्धांतों पर हमारी कार्य करने की प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है।

कुंजी शब्द- जी-20,भारतीय कूटनीति,शिखर सम्मेलन, सर्वसम्मति, सामूहिक कार्रवाई एवं वैश्विक मंदी

प्रस्तावना - 1960 के दशक के अंत तक एशिया अफ्रीका एवम् लैटिन अमेरिका में अनेक छोटे बड़े राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण इन राष्ट्रों की निर्भरता औद्योगिक राष्ट्रों पर थी। यही कारण था कि न केवल विश्व के इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों एवं इनके संगठित मंच गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा धनी एवं निर्धन राष्ट्रों की आर्थिक मामलों एवं नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मामले को 1962 से बार बार उठाया गया। बल्कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की पहल के क्रियान्वयन के रूप में ही संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का छठा अधिवेशन भी 1 मई 1974 को बुलाकर 'कार्यवाही योजना" के ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पास किया गये।

नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श पहला- उत्तर दक्षिण संवाद एवं दूसरा- दक्षिण दक्षिण संवाद का प्रारंभ हुआ। अर्थात् विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग एवं प्रचार प्रसार तथा दक्षिण दक्षिण संवाद का अभिप्राय हैं विकासशील राष्ट्रों के मध्य विचार विमर्श एवं आपसी पर निर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। इस क्षेत्र में निरंतर 1975 से 77 तक चलने वाला अंतर राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन से लेकर 1981 के कानकुन सम्मेलन तक के अनेक प्रयासों के बावजूद विकसित राष्ट्रों की हठधर्मीता के कारण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संवाद की बाधाओं को दूर नहीं किया जा सका।

उद्देश्य एवं महत्व- प्रस्तुत पेपर का उद्देश्य जी- ट्वेंटी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना तथा जी- ट्वंटी में भारत की भूमिका का अध्ययन करना है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से जी ट्वेंटी समूह का गहराई से ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। तथा भारत की अध्यक्षता में जी-ट्वेंटी से भारत सहित वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका के महत्व को रेखांकित करने में सहायता प्राप्त होगी।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध पत्रों में मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्राविधि के साथ- साथ द्वितीयक स्रोत जैसे- किताब, न्यूज़ पेपर, पत्रिका आदि का उपयोग किया गया है।

जी-20 समूह का गठन - सन् उन्होंने 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के समय वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय स्थायित्व आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु व्यवस्थितऔद्योगिकृत,विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित् मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा मिलकर जी-ट्वेंटी समूह की स्थापना की गई थी। अपने गठन के समय से ही जी- ट्वेंटी समूह द्वारा नियमित रूप से वित् मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठकों का आयोजन वैश्विक वित्तीय समाधान तथा स्थायित्व को बढ़ाने के उपायों को प्रोत्साहित करने और सतत्

आर्थिक वृद्धि तथा विकास के उद्देश्य से निरंतर किया जा रहा है। भारत जी-20 समूह का एक महत्वपूर्ण विकासशील राष्ट्र है। जी- ट्वेंटी समूहों जो, अपने प्रारंभिक वर्षों में वित् मंत्रियों का ही मंच था, जिसे 2008 में शिखर सम्मेलन का रूप दिया गया। जिससे राष्ट्र प्रमुखों का प्रतिनिधित्व भी इसमें होने लगा। इस समूह में विकसित राष्ट्रों में जहां अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, कनाडा तथा जापान एवं विकासशील राष्ट्रों में भारत, चीन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील तथा रूस आदि राष्ट्र शामिल हैं।

जी-20 एवं भारत- भारत, जी- ट्वेंटी समूह का एक महत्वपूर्ण विकासशील राष्ट्र है। नवंबर 2022 में वाली शिखर सम्मेलन के अंत में जी- ट्वेंटी समूह की अध्यक्षता का जो हथौड़ा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सौंपा गया था तथा एक दिसंबर को भारत द्वारा जब जी- ट्वेंटी समूह की ज़िम्मेदारी सँभाली गई, वह समूह वैश्विक जनसंख्या का 60% जीडीपी का 85प्% तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% का प्रतिनिधित्व कर रहा था। भारत ने जहाँ एक ओर बाली शिखर सम्मेलन में विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वहीं दूसरी ओर बाली शिखर सम्मेलन में यह भी ठाना था, कि अपनी अध्यक्षता में वैश्विक चुनौतियों में भी वह खरा उतरेगा। इस सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक नेताओं के जमावड़े से कहा कि "कोविड-19 के बाद के दौर के लिए नई व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारत की जी-20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्यवाही उन्मुख होगी। हम साथ मिलकर जी-20 को वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बनाएंगे।" जहाँ इंडोनेशिया की अध्यक्षता "रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रिंागर थीम को लेकर थी, तो वहीं भारत की थीम "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" रही।

रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भू राजनैतिक तनाव, खादानन संकट, ऊर्जा संकट, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की धीमी रफ़्तार, विकासशील राष्ट्रों के समक्ष अपना वजूद बचाने का संकट,70 से अधिक राष्ट्रों पर बढ़ता कर्ज़ संकट तथा 2023 मैं ख़तरनाक वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका संपूर्ण विश्व के समक्ष थी। कोविड-19 के पश्चात की इस विखंडित एवं विश्रृंखल दुनिया ने भारत को निश्चित ही एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया, कि वह इन तमाम प्रमुख मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रयास करने की अगुवाई करें। साथ ही विकासशील राष्ट्रों के एजेंडे का चैंपियन बनकर उभरे। एक सच्चे वैश्विक नेता के रूप में भारत स्थापित हो।

कहना नहीं होगा कि भारत की सधी हुई कूटनीति के चलते जी- ट्वेंटी समिति के माध्यम से महत्वपूर्ण सफलताएं भारत को प्राप्त हुई जैसे -

- भारतीय कूटनीति का उद्देश्य समिट में सार्वजनिक सहभागिता स्थापित करने का था। आंकड़े गवाह है कि भारत ने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 60 शहरों में 220 बैठकें की। जिसके पीछे मूल विचार यह था कि, जी- ट्वेंटी को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाया जाए। जिसके अंतर्गत इसमें लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में सहभागिता की। भारत सरकार के अनुसार जी-ट्वेंटी के लोकतंत्रीकरण हेतु निश्चित ही

इसे बंद कमरों की बैठकों से बाहर लाना होगा, क्योंकि यदि जी- ट्वेंटी के निर्णयों से लोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित ही उसकी प्रक्रिया में भी जन भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और यह भारत ने करके दिखाया है।

- जी- ट्वेंटी समिट में 43 वैश्विक नेता शामिल हुए। जिनमें 20 राष्ट्राध्यक्ष ,9 मेहमान राष्ट्र तथा 14 वैश्विक एजेंसियों के प्रमुख भी थे। जो अन्य शिखर सम्मेलनों से कहीं ज़्यादा बड़ा जमावडा था। भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक मामलों पर फ़ोकस करते हुए जहाँ समिति के एजेंडे में चर्चा हेतु क्लाइमेट चेंज, फ़ाइनेंसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंगिक समानता, क्रिप्टो करेंसी, बहुपक्षीय समस्याओं के सुधार और कर्ज़ में राहत आदि विषयों को शामिल किया, तो वहीं अंत में जारी किया गया दिल्ली घोषणापत्र जो 34 पेज का था, उससे भारत ने अपने मंतव्य को कहीं न कहीं सुनिश्चित किया।
- जी- ट्वंटी के संदर्भ में भारत की कूटनीतिक सफलता का मज़बूत उदाहरण है अफ़्रीकी यूनियन की सदस्यता के प्रस्तावों की अगुवाई करना। जो यह दर्शाता है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में कि "यह ग्लोबल साऊथ के लिए एक व्यापक संदेश है और उनकी ज़रूरी चिंताओं का समाधान भी। नई दिल्ली को इस उपलब्धि पर गर्व है कि यह केवल नीतिगत विचार ही नहीं बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक भूल सुधार की भावना भी थी क्योंकि पश्चिम केवल समावेश की बात भर करता है, लेकिन भारत ने यह दिखाया है कि उसे अमल में कैसे लाया जाता है।" भारत ने जी- ट्वेंटी की अध्यक्षता मिलने के प्रारंभ से ही यह मन बना लिया था कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरेगा और भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने अफ़्रीकान्स यूनियन के प्रेसिडेंट को गले लगाया तो विश्व को एक तस्वीर में दो संदेश प्राप्त हुए। पहला मोदी का नेतृत्व तथा दूसरा शी जिनपिंग की अनुपस्थिति।
- भारत ने ऐसे माहौल में सर्व सम्मति निर्मित करने में सफलता प्राप्त की, जब पाश्चात्य राष्ट्र एवं रूस इस समिट में एक स्थाई मानसिकता से आए थे। जिसमें वे ज़रा भी बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। जिसके चलते अन्य विंदू भी बेपटरी हो सकते थे। अंत में एक ऐसा घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें सभी पक्ष सहमत हो गए। वर्तमान के अत्यंत ध्रुवीकृत एवं विभाजित देशो मैं सर्वसम्मति बनाना अपने आप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहाँ पश्चिम को रूस एवं चीन से समस्या है तथा चीन को जापान एवं दक्षिण कोरिया से। ऐसे में भारत ने वर्तमान में अत्यधिक ध्रुवीकृत एवं विभाजित विश्व में सर्वसम्मति बनाकर दुष्कर कार्य करके दिखलाया है।
- जब समिट से किसी को भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं थी। कलह एवं दिखावा था। तब कोविड-19 महामारी से यह धारणा और सशक्त हो चुकी थी, जब जी- ट्वेंटी वैक्सीन की डिलिवरी भी सुनिश्चित नहीं कर पाया था और न ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामलों में सुरक्षा दे पाया था। ऐसे में जी- ट्वेंटी समूह के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे थे। तब ऐसे में भारत की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व को इसमें विश्वास के अभाव की बात

की। इसे सुधारने की कोशिश की। इस समिट की प्रासंगिकता बनाने एवं इसके प्रति विश्वास को वापस प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।भारतीय कूटनीति की बड़ी सफलता यह भी रही, कि रूस एवं पश्चिम दोनों ने भारत का अभिवादन किया। यद्यपि चीन इससे ज़रूर नाख़ुश हुआ होगा। निसंदेह भारत ने विश्व के समक्ष जी- ट्वेंटी की उपयोगिता, इसकी रक्षा तथा विस्तार की आवश्यकता को समझाने में भी सफलता प्राप्त की।

- वर्तमान में भारत के वैश्विक स्तर पर लगभग प्रत्येक ब्लॉक से अच्छे संबंध हैं। कोविड-19 के पश्चात वैक्सीन मैत्री ने भी भारत के विकासशील राष्ट्रों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया है। जब चीन अफ्रीका पर अपना प्रभाव बढ़ाने की फ़िराक़ में है, तब समिति के पहले ही निर्णय (अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित करना) मैं भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक चतुराईपूरण युक्ति के रूप में सफलता कहीं जा सकती है।
- ऐसे ही रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के नपे- तुले व्यवहार के कारण ही भारत रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ- साथ अमेरिका एवं अन्य पाश्चात्य राष्ट्रों से भी संबंध स्थापित करने में सफल रहा है। वही क्वाड एक ऐसा समूह है, जिसमें (भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं) को पुनः मज़बूती देकर चीन को भी एक सख़्त संदेश दिया गया है, कि वह भारत के प्रति आक्रामकता तथा समूचे भारत- प्रशांत क्षेत्र में अपने वर्चस्व की कोशिशों से बाज़ आए। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि वैश्विक राष्ट्र अपने निजी स्वार्थों के लिए ही सही, लेकिन भारत से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं।
- जी- ट्वेंटी समिट में जिस "भारत- मध्यपूर्व- इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है, निश्चित ही उससे भारत की इकोनॉमक ग्लोबल ताक़त बढ़ेगी।" "जीं- ट्वेंटी का अध्यक्ष बनने के पश्चात भारत ने दुनिया के समक्ष GDP केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया है" समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक ये चार शब्द जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारतीय दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली डिक्लेरेशन (NSDL) जिसे सभी जी- ट्वेंटी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है, इन सिद्धांतों पर हमारी कार्य करने की प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है
- समावेशी की भावना के कारण ही भारत जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ (A U), जिसमें 55 अफ्रीकी राष्ट्रों को इस समूह में जगह दिलवाने में सफल रहा है। भारत ने "वॉयस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ" समेत जो (अपने आप में अनूठी बैठक थी) को भुलाकर एक नवीन शुरुआत की है। इसकी दो बैठकों के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने में सफल रहा है। समावेशिता के भाव के कारण इस आयोजन में घरेलू प्रभावों के साथ- साथ लोक अध्यक्षता का स्वरूप भी भारत ने प्राप्त किया। जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र

शासित प्रदेशों में लगभग 1.4 विलियन नागरिकों ने सहभागिता की, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की दृष्टि से उचित ही था।

- 2030 के एजेंडे को दृष्टि में रखते हुए भारत ने सतत् विकास लक्ष्य में तेज़ी लाने के लिए जी-ट्वंटी का 2023 का एक्शन प्लान भी प्रस्तुत किया। जिसके अंतर्गत भारत के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण स्थिरता आदि परस्पर और संबंधित विषयों पर व्यापक ऐक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण को अपनाया गया। जी-20 के माध्यम से भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण को अपनाया है।जी -20 के माध्यम से भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोज़िट्री को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जो वैश्विक तकनीकी समूह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसी प्रकार "वन अर्थ" की भावना से प्रेरित भारत द्वारा जी -ट्वेंटी घोषणा में ही 2030 तक रिन्युएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को तीन गुना करने का महत्वाकांक्षी आवाहन विश्व से किया गया है। निश्चित ही भारतीय मूल्यों के अनुरूप सतत् विकास के लिए जीवनशैली के माध्यम से विश्व हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से लाभ प्राप्त कर सकता है। भारत के प्रयास से ही अरुण पुरी घोषणा पत्र में जलवायु, न्याय तथा समानता के लिए पहली बार विकास के वित्तपोषण से जुड़ी कुल राशि में अत्यधिक बढ़ोतरी की ज़रूरत को भी स्वीकार किया गया है। जो अरबों डॉलर से खरबों डॉलर तक पहुँच गया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में महिला- पुरूष समानता पर केंद्रित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन की बात को भी विश्व ने स्वीकार किया है।
- भारत के लिए यह गर्व की बात है, कि उसकी अध्यक्षता में निसंदेह असाधारण उपलब्धियां भारत ने हासिल की है। इस दौरान जी- ट्वेंटी ने 87 परिणाम प्राप्त किए हैं तथा 118 दस्तावेज़ अपनाए हैं। जो अतीत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक हैं। भारत ने एक ओर जहाँ बहुपक्षवाद में जान फूंकी, तो वहीं दूसरी ओर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मज़बूती प्रदान की है। विकास की तरफ़दारी करते हुए महिला सशक्तीकरण का नारा भी बुलंद किया है।

निष्कर्ष -इस प्रकार कहा जा सकता है, कि जी- ट्वेंटी जो विकसित और विकासशील राष्ट्रों का समूह है ,भारत ने इसकी अध्यक्षता करते हुए अपनी कूटनीति से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयां प्राप्त हुई है। भारत की यह कूटनीतिक सफलता ही है कि,वर्तमान में वह रूस- यूक्रेन युद्ध हो, या भारत- प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व की लड़ाई हो, सभी क्षेत्रों में भारत ऐसी स्थिति में आ चुका है, जिससे वैश्विक स्तर पर राष्ट्र अपने निजी स्वार्थ से ही सही, फिर भी वे भारत से संबंध बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वर्तमान में भारत निसंदेह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मज़बूत स्थिति में हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. अरुण पुरी: (2022,14 दिसंबर), प्रधान संपादक की कलम से,इंडिया टुडे,पेज ,3.
2. कांत अमिताभ: (2022 14 दिसम्बर), भारत का वक़्त, पेज, 19-21
3. फडिया,बी.एलऔरफडियाके.: (2020),अंतरराष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा,
4. शर्मा,पलकी : 2023, सितंबर14 ,दैनिक भास्कर,जी-20 की बड़ी कामयाबी के पाँच सबसे प्रमुख कारण, पेज, 4
5. वर्मा, पवन के : 2023, सितंबर 10,दैनिक भास्कर,जी-20 पर सवॉल उठाना विपक्ष की समझदारी नहीं, पेज, 4
6. मोदी, नरेंद्र : प्रधानमंत्री,2023,नवंबर,30,दैनिक भास्कर,जी-20 की अध्यक्षता और नये बहुपक्षवाद की शुरुआत, पेज, 4